

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

राजस्व अनुमति—२

देहरादून: दिनांक: २० फरवरी, 2014

विषय:—श्रीमती मालती राय पत्नी श्री प्रदीप राय, निवासी जानकीपुरम, लखनऊ (उ०प्र०) को ग्राम स्यालीस्टेट तहसील गरुड, जिला बागेश्वर में पर्यटन प्रयोजनार्थ (रिजार्ट की स्थापना) हेतु 0.464 है० भूमि क्य की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3373/V-27 स्टाम्प-भूक्रय/2011 दिनांक 18.07.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल श्रीमती मालती राय पत्नी श्री प्रदीप राय, निवासी जानकीपुरम, लखनऊ (उ०प्र०) को ग्राम स्यालीस्टेट तहसील गरुड, जिला बागेश्वर में पर्यटन प्रयोजनार्थ (रिजार्ट की स्थापना) हेतु 0.464 है० भूमि क्य की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जर्मांदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा-154(4)(3)(क)(II) के अन्तर्गत पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति/सहमति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1— केता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अर्ह होगा।

2— केता द्वारा क्य की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्य विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (रिजार्ट निर्माण) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्य, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

3— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्य से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

3/

4— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकरणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5— शासन द्वारा दी गई भूमि क्य की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6— जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि क्य हेतु प्रस्तावित भूमि, समस्त वर्जनाओं से विमुक्त है तथा सम्बन्धित भूमि अथवा उसका कोई भी अंश अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों से सम्बन्धित नहीं है अर्थात् प्रश्नगत भूमि क्य में किसी भूमि सम्बन्धी कानून विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है।

7— सम्बन्धित क्षेत्र/भूमि की भूगर्भिक दशा एवं परियोजना के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण के पर्यावर्णीय प्रभाव के अध्ययन/आंकलन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

8— सम्बन्धित भूमि व उस पर प्रस्तावित निर्माण के सन्दर्भ में वन संरक्षण अधिनियम/वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, एफोएओआर० रूल्स अथवा अन्य कोई अधिनियम/नियम लागू होने/न होने तथा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी किन्हीं विनियमों के परिप्रेक्ष्य में वांछित कार्यवाही/अनुपालन सम्बन्धित निवेशक द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

9— परियोजना प्रस्ताव में दर्शित इकाई के डिजाइन, आकार/प्रकार, निवेश, सीमा, निर्माण अवधि एवं अन्य संगत प्राविधानों/अभिकथनों का निवेशक द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10— स्थापित की जानी वाली पर्यटन इकाई में स्थानीय युवकों/बेरोजगारों को रोजगार दिया जायेगा।

11— परियोजना में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग एवं पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

12— इकाई द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पर्यटन इकाई की स्थापना से इकाई द्वारा जल व अन्य स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने में स्थानीय समुदाय/पंचायत को कोई आपत्ति न हो।

13— भूमि पर पर्यटन विकास/व्यवसायिक निर्माण करने से पूर्व भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन भी कराया जाना होगा।

14— सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

15— किसी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि क्य के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

16— भूमि का विक्य अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्य किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

17— योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियों/स्वीकृतियों प्राप्त कर ली जायेगी।

18— उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी यथा समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

प०प०सं-५६ / समदिनांकित / 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2— आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।

3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4— श्रीमती मालती राय, पत्नी श्री प्रदीप राय, 7/501 दीपक, डीलक्स सहारा ग्रेस, जानकी पुरम लखनऊ (उ०प्र०)।

5— निदेशक एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।

6— प्रभारी, मीडिया सेन्टर उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।